

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Labour in the Ministry of Labour and Employment (Shri Hathi): (a) A scheme for training in Building and Construction industry is still under consideration.

(b) Does not arise.

Public Undertakings

1477. **Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) how many public undertakings have appointed Liaison officers at various places in India and abroad;

(b) total number of such officers and the annual expenditure on such officers; and

(c) the functions, need, utility and purpose of such officers?

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दण्डकारण्य परियोजना

१४७८. श्री बड़े : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी जीपें १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ और १९६२ में अब तक दण्डकारण्य परियोजना के लिये खरीदी गई हैं ;

(ख) उनमें से कितनी जीपें ठीक चलती हैं ;

(ग) कितनी जीपें खराब होकर पड़ी हैं ;

(घ) १९५८ के पश्चात् कितनी जीपें नीलाम से बेची गईं और कितने-कितने में नीलाम हुईं ;

(इ) जो जीपें खराब हो गई हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है और सरकार उनको काम में लेना चाहती है या नहीं ; और

(च) कितनी जीपें खो गई हैं जिन का पता नहीं चल सकता ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Debt against Sholapur Spinning and Weaving Mills

1479. { Shri Sonavane:
Shri P. N. Kayal:
Shri Siddiah:

Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) the amount of loan outstanding against the Sholapur Spinning and Weaving Mills Ltd., Sholapur; and

(b) the steps taken so far to recover it?

The Minister of International Trade in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Manubhai Shah): (a) The Government of India have not directly advanced any amount to the Sholapur Spinning and Weaving Company Limited, Sholapur. The mills however owe the Government of Maharashtra a sum of 94 lakhs together with interest at the rate of 5½ per cent of per annum from December, 1956. Out of this amount a sum of Rs. 46.5 lakhs was advanced by the Government of India to the then Government of Bombay for the specific purpose of relending the same to the mills.

(b) Due to the weak financial position of the mills it has not been possible for the Government to take any concrete steps for recovery of the

loan. The state of affairs in the mills is at present under inquiry by an Investigation Committee which was set up on the 16th July, 1962. Further action will depend on the findings and recommendations of the Investigation Committee.

Tanning Industry

1480. Shri Mohammad Tahir: Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tanning Industry is working below the installed capacity;

(b) if so, the reason thereof; and

(c) whether Government is importing raw hides from other countries?

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) Yes. The ratio of actual production to the installed capacity is 60 per cent in the large scale sector, 54 per cent in the small scale sector and 81 per cent in the cottage and village scale sector.

(b) Shortage of hides and skins is the main reason for tanneries working below their installed capacities.

(c) No. But imports of raw hides are allowed on private account to established importers and actual users upto 100 per cent of the best year's imports.

कांगड़ा में चाय का सहकारी कारखाना

१४८१. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारंकित प्रश्न संख्या १३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने सहकारी चाय फैक्टरी कांगड़ा जिले में लगाने की योजना केंद्रीय सरकार को भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने चाय बोर्ड द्वारा ३ लाख ६० का ऋण दिया जाना स्वीकार कर लिया है।

(ख) मीडा में ५००,००० ६० की पूंजी लागत पर एक चाय फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव है। इसका प्रबन्ध एक सहकारी समिति करेगी। इस फैक्टरी की उत्पादन क्षमता २००,००० पौंड काली चाय होगी तथा इसमें वैधान्तर इलाके में पैदा होने वाली सब चाय तैयार की जा सकेगी। इस सहकारी समिति की हिस्सा पूंजी का व्यौरा नीचे दिया गया है :

	₹०
(१) सहकारी समिति के सदस्यों का अंशदान	५०,०००
(२) समिति के हिस्से खरीदने के लिये पंजाब सरकार की हिस्सा पूंजी	५०,०००
(३) पंजाब सरकार के जरिये चाय बोर्ड द्वारा समिति को दिया गया ऋण	३००,०००
(४) समिति को राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण	१००,०००

योग	५००,०००

सहकारी फैक्टरी स्थापित करने के लिये वित्तीय आवश्यकता का अनुमान नीचे दिया जा रहा है :—

(१) कुल अचल सम्पत्ति:	₹०
(१) भूमि की कीमत	५,०००
(२) इमारत की कीमत	१४०,०००
(३) मशीनों का मूल्य	२५०,०००

योग	३९५,०००
